लघु और मध्यम शहरों के समेकित विकास के अन्तर्गत शहरों की पहचान किया जाना

5755. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु व मध्यम शहरों के समेकित विकास के अन्तर्गत लघु और मध्यम शहरों की पहचान कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ शहर-वार तथा राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र प्रवर्तित लघु तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93) के दौरान लाभान्वयन हेतु 25 राज्य सरकारों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में कुल 536 कस्बों का निर्धारण किया है। जिसके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं; **(नीचे देखिए)**; और

(ग) आई० डी० एस० एम० टी० योजना के तहत चूंकि राज्य सरकारों को केवल उदार ऋण दिये जाते हैं; अतः किसी राज्य अथवा नगर/कस्बा विशेष के लिये कोई धन निर्धारित नहीं है। आई० डी० एस० एम० टी० दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना रिपोर्टें प्राप्त होने पर निधियां रिलीज की जाती हैं। निर्धारित किये गये 536 कस्बों में से आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 232 कस्बे पहले ही लाभान्वित किये जा चुके हैं और 44.75 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा आई० डी० एस० एम० टी० के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना के (1992-93) के दौरान लाभान्वयन के लिए निर्धारित कस्बों की संख्या।

क्रम सं०	राज्य का नाम	निर्धारित कस्बों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	33
2.	अरुणाचल प्रदेश	12
3.	असम	17
4.	बिहार	40
5.	गोवा	3
6.	गुजरात	10
7.	हरियाणा	10
8.	हिमाचल प्रदेश	8
9.	जम्मू एवं काश्मीर	9
10.	कर्नाटक	72
11.	केरल	20
12.	मध्य प्रदेश	38
13.	महाराष्ट्र	57
14.	मणिपुर	5
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	20
17.	नागालैंड	4
18.	उड़ीसा	31
19.	पंजाब	10
20.	राजस्थान	30
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	30
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	41
25.	पश्चिम बंगाल	25
26.	पाण्डिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	5
	योग :	536

Implementation of Low Cost Sanitation Scheme in Vijayawada

5756. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Union Government propose to implement low cost sanitation scheme in Vijayawada;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of the participation of Union and State Governments and Vijayawada Municipal Corporation in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) to (c) Yes, Sir. A scheme for construction of 18,725 low cost sanitary latrines with a project cost of Rs. 688.61 lakhs has been sanctioned for Vijayawada. The Central Government subsidy is Rs. 190.68 lakhs. The HUDCO loan commitment is Rs. 402.1 lakhs. The balance cost is to be met by the individual beneficiaries. The State Government provides guarantee for the HUDCO loan. The Municipal Corporation is the implementing agency for execution of this project.

गैर-सरकारी संगठनों से सहायता लिया जाना

5757. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस० एस० सुरजेवाला:

क्या **शहरी कार्य और रोज़गार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी गरीबी की समस्या को सुलझाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सहायता लेने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों को इस संबंध में कोई सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) यद्यपि, शहरी निर्धनता की समस्या को हल करने में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता लेने के लिए कोई विशेष स्कीमें नहीं हैं फिर भी सरकार की सलाह पर कार्यान्वयन एजेंसियां, निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यूबीएसपी) और नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) सहित निर्धनों के लिए सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन में उपलब्धता और कार्यनिष्पादन की शर्त पर गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल कर रही हैं।

(ग) राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा पता लगाए गए ऐसे गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए निधियां राज्यों/संघ शासित राज्यों को रिलीज की जाती हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के ब्यौरे अनुलग्नक में हैं।

Development of Cities of Andhra Pradesh

5758. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of the schemes launched by the Union Government and the Housing and Urban Development Corporation for the development of small and medium cities of Andhra Pradesh; and

(b) the total funds earmarked for this purpose during 1994-95 and the actual expenditure incurred thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) Under the Scheme of Integrated Development of Small and Medium Towns (IDSMT), 60 towns of Andhra Pradesh have been covered since the inception of the Scheme in 1979 till date and a sum of Rs. 17.76 crores released. The schemes covered include Markets and Shopping Complexes, Roads, Drainage works, Sites and Services, Bus stands and other infrastructural facilities.

(b) Under the Scheme of IDSMT, since only soft loans are given to State Governments there is no earmarking of funds for any particular State. Depending upon receipt of project reports conforming to IDSMT guidelines, funds are released. Accordingly, no specific allocation has been earmarked for Andhra Pradesh during 1994-95. The expenditure incurred under IDSMT by the State Government upto December, 1993, for which information is available, is Rs. 21.66 crores.